(d) The following steps are being taken to improve the return from milk production:—

(1) Genetic improvement of nationally important cattle breeds by selective breeding in their hometracts and up-grading in other selected areas;

(2) Cross-breeding of non-descript cattle with exotic dairy breeds:

(3) Genetic improvement of important buffaio breeds by selective breeding and upgrading of non-descript buffaloes in other areas for improvement in milk yields;

(4) Development of feed and fodder resources;

(5) Organisation of effective animal health services to support the production programme; and

(6) Implementation of Operation Flood Programme.

देश में प्रति पशु दुग्ध का औसत उत्पादन

1554. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में तीसरा स्थान है जबकि विश्व भर में पायी जाने वाली कुल भैंसों में से 50 प्रतिशत भारत में पायी जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में दुध का उत्पादन तो बढ़ा है परंतु प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की दर में विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में देश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की दर क्या है और भविष्य में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी नहीं । दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है ।

(ख) और (ग) जी हां । यह सही है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है । वर्तमान उत्पादन 58.6 मिलियन टन है । प्रति गाय 1.158 किलो ग्राम प्रति दिन के हिसाब से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है । नस्ल वार दुग्ध उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते । फिर भी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 70 मिलियन टन कुल दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

देश में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता

1555. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने सरकार को देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री ने मार्च, 1993 में नई दिल्ली में "कृषि में उभरते मुद्दे" पर एक सेमिनार का आयोजन किया था । चैम्बर ने सेमिनार की मसौदा सिफारिशें जानकारी हेतु भेज दी हैं । उत्पादकता से संबंधित सिफारिशें वर्षासिंचित और बारानी क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र-प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर देने, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करने पर उचित ध्यान देने, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारी-कृषि का संगठन करने, छोटी जोतों हेतु उचित प्रौद्योगिकी तथा नवीनतम हाई-टेक जैव-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए नए किसानों की खेती में वृद्धि करने पर बल देती है ।

14 मई, 1993 को सभा-पटल पर रखे गए कृषि नीति संकल्प के प्रारूप को तैयार करते समय इन सिफारिशों पर विचार किया गया था ।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण

1556. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी संसदीय समिति ने देश के कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण की गिरती हुई हालत पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त समिति ने अगले पांच वर्षों के लिए कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र में 1,25,000 करोड़ रूपए की राशि का निवेश करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) आठवीं योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि कुल निवेश में कृषि के हिस्से को सातवीं योजना के 11.23 प्रतिशत से बढ़ाकर आठवीं योजना में 18.65 प्रतिशत कर दिया जाए ।

आठवीं योजना के दौरान 7,98,000 करोड़ रूपए के कुल निवेश में कृषि क्षेत्र में 1,48,800 करोड़ रूपए का वास्तविक निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है ।

कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण न केवल कृषि मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से होता है, बल्कि ज्यादातर ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है । कृषि एवं सहकारिता विभाग के चालू कार्यक्रमों को भी अब इस तरह से चलाया जा रहा है कि लागतों में कटौती की जा सके और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सके ।

सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में कृषि उत्पाद

1557. **श्री अन्तराय देव शंकर दवे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार सूखे की स्थिति रहने के परिणामस्वरूप पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन-किन जिलों में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले पांच वर्ष की अवधि अर्थात 1988-89 से 1992-93 तक के दौरान, गुजरात राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में दो वर्षों, अर्थात 1990-91 और 1991-92 के दौरान फसल बुरी तरह प्रभावित हुई ।

(ख) व्यावहारिक रूप में इस क्षेत्र के सभी जिलों अर्थात् गुजरात राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण 1990-91 और 1991-92 के दौरान विभिन्न अंश में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

Protection to Pepper cultivator

1558. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI J. S. RAJU:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to answer to Starred Question 266 given in the Rajya Sabha on the 14th May, 1993 and state:

(a) the quantity of pepper purchased under market intervention scheme;

(b) whether the scheme was extended beyond the 30th June, 1993;

(c) whether the market price of pepper did reach the desired price of Rs. 33/- per kg. for fair average quality in the commercial market of Kerala during the scheme;

(d) if so, details thereof: if not. reasons therefor;

(e) what is the present market price of fair average quality of pepper in the commercial market of Kerala:

(f) whether there is any proposal before Government to intervene in the market and to procure fair average quality of pepper at Rs. 33/- per kg. and export the same; and

(g) if not, what other steps are being taken to improve the market price of pepper to help marginal farmers in Kerala from economic servitude ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) A targetted quantity of 3000 metric tonnes of black, pepper was purchased by the NAFED and the State designated agency under Market Intervention Scheme.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) to (f) The present market price of fair average quality of pepper in Kerala markets is around Rs. 30.50 per kg. as against the prevailing price of Rs. 25.28 before implementation of Scheme. No proposal to render further help to black pepper growers has been received from the State Government.

(g) Integrated, programme for the development of the spices is being implemented for increasing the production and productivity of spices including pepper to make it competitive in the international market.

Drought hit areas

1559. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of villages and towns in Madhya Pradesh, Gujarat Rajasthan, Bihar, Orissa and the other States and Union Territories declared drought hit this year State/ U.T.-wise;

(b) the extent of scarcity estimates with respect to different States and territories: and the Central and State relief measures taken to help the victims; and

(c) whether any long term measures are proposed to be taken for the drought hit areas ?